



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]
No. 613]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2000/अग्रहायण 16, 1922
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2000/AGRAHAYANA 16, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2000

सा. का. नि. 909 (अ).—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित सारणी के कालम (2) में वर्णित स्थान पर इस सारणी के कालम (3) में तदनु रूप प्रविष्टि में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करती है।

सारणी

क्रम सं०	स्थान, जहां पर अधिकरण स्थापित किया गया है	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1.	“महाबैंक भवन” सी-3, एन-1 टाउन सेन्टर सिडको, औरंगाबाद-431003	महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद, नांदेड, जालना, बीड, परभाणी, उस्मानाबाद, लातूर, अहमदनगर, जलगांव, धुले, नन्दूरबार, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर एवं सांगली जिले।

तदनुसार, उपर्युक्त कालम (3) में उल्लिखित क्षेत्र दिनांक 16 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं० 13/2/95 डी आर टी द्वारा स्थापित ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई के क्षेत्राधिकार से हटा दिए जाएंगे।

[फा० सं० 39/1/2000-डी आर टी]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(BANKING DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2000

G. S. R. 909(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby establishes the Debts Recovery Tribunal at the place mentioned in column (2) of the Table below, to exercise jurisdiction within the areas specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl No	Place at which Tribunal is established	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	“MAHABANK BHAWAN” C-3, N-1, TOWN CENTRE CIDCO, AURANGABAD-431003.	Aurangabad, Nanded, Jalna, Beed, Parbhani, Osmanabad, Latur, Ahmednagar, Jalgaon, Dhule, Nandurbar, Pune, Satara, Kolhapur, Solapur and Sangali Districts of Maharashtra.

Correspondingly, the areas, mentioned in Column (3) above would get deleted from the jurisdiction of Debts Recovery Tribunal, Mumbai set up vide Notification No. 13/2/95-DRT dated 16th July, 1999

[F. No. 39/1/2000-DRT]

U K. SINHA, Jt. Secy.